Creation of farm produce Marketing Authority

1813. SHRI SHAMIM HASHMI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether prices of various farm produce including milk and fish and meat have been escalating specially in Delhi;

(b) whether Government would immediately create a Farm Produce Marketing Authority to fix fair prices for producers and consumers in order to stop present stranglehold of middlemen;

(c) whether role of ensuring quality control would be also handed over to this Authority apart form fixation of producer and consumer prices;and

(d) whether interests of producers and consumers will be effectively represented on this Authority which would fix prices on a continued weekly/fortnightly/ monthly or longer basis for all farm produce?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHYAM LAL YADAV) : (a) The retail prices of foodgrains, milk, fish and meat have remained steady or shown only marginal or moderate fluctuations during the last few months in Delhi and other centres like Bombay, Madras, Kanpur, Calcutta and Chandigarh.

(b) to (d) There is no such proposal under consideration of the Government. However, the intertests of producers and consumers are kept in view by the Government while fixing procurement/ support prices in respect of important agricultural commodities and prices of essential items like rice and wheat supplied through the Public Distribution System.

Timings of Fair Price Shops in Delhi

1814. SHRI N.RAJANGAM: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) what is the time for opening of Fair Price Shops in Delhi;

(b) whether it is a fact that Fair Price Shop owners in Mahipalpur village, Delhi, open their shops only for two hours in a day; and

(c) whether Government propose to conduct an inquiry into the matter and punish such shopowners?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI D. L. BAITHA): (a) The timings for opening of Fair Price Shops in Delhi are us under:—

9.00 A.M. to 1.00 P.M.
3.30 P.M. to 7.30 P.M.

(b) No, Sir

(c) Does not arise.

Buffer stock of foodgrains

1815. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the country's foodgrains stocks are at a precariouly low level; and

(b) if so, the details thereof and the action to be taken with regard to the maintenance of foodgrain stocks?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI D. L. BAITHA): (a) and (b) The stock position of foodgrains with public agencies as on 1st February, 1989 at 9.25 million tonnes comprising 4.30 million tonnes of wheat, 4.86 million tonnes of Rice and 0 09 million tonnes of

coarse-grain, is at a low level compared to previous years. However, there is regular replenishment of stocks through procurement operations in the country and the procuring agencies have been advised to maximise the procurement. The option of imports of foodgrains is also kept open, in case the need is felt on review of stocks. Simultaneously, the available stocks are being utilized judiciously to meet the reasonable requirements of the Public Distribution Systems.

राजस्थान में टी.वी. नेटवर्क का विस्तार

1816. **श्री भंवर लाल पंवार:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, राजस्थान के ग्यारह जिलों में टी.वी. रिले केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव था लेकिन गत चार वर्षों के दौरान केवल पाली और नागौर जिले में ही टी.वी. केन्द्र स्थापित किये जा सके हैं;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान के शेष स्थानों अर्थात चुरू, पिलानी, झुन्झुनू, सीकर, सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और रावत भाटा में कब तक टी.वी. केन्द्र स्थापित कर दिये जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या सरकार राजस्थान के सभी टी.वी. केन्द्रों से क्षेत्रीय भाषा और लोक गीतों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू करने का विचार रखती है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच॰के॰एल॰ भगत): (क) और (ख) राजस्थान राज्य से संबंधित दूरदर्शन की अनुमोदित सातवीं योजना में अनूपगढ़, बाड़मेर, बूंदी और जैसलमेर में एक-एक कुल मिलाकर 4 उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने तथा बांसवाड़ा, चितौड़गढ़, चुरू, डूंगरपुर, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, पाली, पिलानी, सवाई माधोपुर, सीकर और सिरोही में एक-एक कुल मिलाकर 12 अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने; रावतभाटा में एक अति अल्प शक्ति (2×10 वाट) ट्रांसमीटर स्थापित करने तथा लालसोट में दूरदर्शन ट्रांसपोजर लगाने की स्कीमें शामिल हैं। जबकि बांसवाड़ा, चितौड़गढ़, डूंगरपुर, झुंझुनू, नागौर, पाली, पिलानी और सिरोही के अल्प शक्ति ट्रांसमीटर और रावतभाटा का अति अल्प शक्ति ट्रासमीटर पहले ही चालू हो गए हैं और शेष 4 अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों को आगामी दो महीनों में चालू किए जाने की उम्मीद है, लालसोट का ट्रांसपोजर 1989 के अन्त तक चालू किए जाने की उम्मीद है। उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों की स्थापना की प्रक्रिया में लम्बा समय लग जाता है और इनकी स्थापना तथा इनको चालू करना इन बातों पर निर्भर करता है—अपेक्षित उपकरण की सप्लाई के लिए स्वदेशी निर्माता को लगाने वाला समय, योजना राशि का वार्षिक आवंटन और विभिन्न स्थानों में आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था। उपर्युक्त स्कीमों के कार्यान्वयन से राजस्थान के सभी जिलों के पूर्णतया या अंशतया दूरदर्शन सेवा से कवर हो जाने की उम्मीद है।

(ग) इनसेट-2 समय संरचना के दौरान अपेक्षित सुविधाओं की उपलब्धता पर राजस्थान के सभी दूरदर्शन ट्रांसमीटरों को प्रारंभिक (प्रादेशिक) सेवा कार्यक्रमों को रिले करने के लिए दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर से जोड़ने का विचार है।

1817. [Transferred to the 27th March, 1989]

ऊबड़-खाबड़ भूमि को समतल करने के लिए मध्य प्रदेश के आदिवासियों को सहायता

1818. **श्री अजीत जोगी:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के आदिवासियों को झूम खेती के नियंत्रण के लिए वर्ष 1987-88 से शत-प्रतिशत अनुदान दे रही है, यदि हां, तो क्या सरकार उसी प्रकार मध्य प्रदेश के आदिवासियों को भी वहां की ऊबड़-खाबड़ भूमि को समतल करने के लिए शत-प्रतिशत मदद देने का विचार रखती है, और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार के पास ऊबड़-खाबड़ भूमि के कारण कम आय की स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई योजना है?